मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी किया जाना

1775. **श्री राम जेठमलानी: क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कह सच है कि देश में सभी मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने हेतु अगस्त, 1993 में अनुदेश जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पहचान-पत्र को अंतिम रूप से जारी करने हेतु सरकार द्वारा अन्तिम तारीख निश्चित की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इसकी अन्तिम तारीख क्या थी; और

(घ) देश में पहचान-पत्रों को जारी करने के लिये कुल कितनी धनराशि अब तक खर्च की गयी है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने, स्कीम को पूरा करने के लिए मूलतः अंतिम तारीख 30 नवम्बर, 1994 नियत की थी। तथापि, यह अंतिम तारीख समय-समय पर बढ़ाई जाती रही और पिछली बार इसे 31 मार्च, 1996 तक बढ़ाया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा कोई नई अंतिम तारीख अभी तक नियत नहीं की गई है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने फोटों पहचान-पत्रों की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को अब तक लगभग 423 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है।

Ban on Foreign Law Companies

1776. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state.

(a) whether the entry of foreign law companies is banned into the country at present;

(b) if so, the details of the policy of Government in this regard;

(c) whether a number of foreign law firms are operating in the country despite ban;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the reasons for their operations in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) to (e) The Reserve Bank of India have informed that three Foreign Law Firms viz. M/s Chadbourne & Parke Associates, M/s White & Case and M/s. Ashurst Morris Crisp have been granted permission under section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 to open their Liaision Offices at Bombay and New Delhi to act as a communication channel i.e. to correspond between their Head Offices and parties in India. They are not permitted to practice law in India.

Court Management Project for Speedy Disposal of the Cases

1777. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
SHRI YERRA NARAYANASWAMY:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state.

(a) whether the Andhra Pradesh High Court is contemplating for planning a court management project for speedy disposal of civil cases which have been pending with the courts;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to initiate such scheme in all the High courts for speedy disposal of pending civil cases?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.